

प्रतिलिपि आदेशादिनांक 1-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिखरे सदस्य
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क० नि० 1234-तीन/14 विरुद्ध
आदेशादिनांक 22-7-2000 पारित द्वारा अर कलेक्टर जिला उत्तरप्र
प्रकरणक्रमांक 289/स्व प्र०/नि०/अ-19/99-2000.

श्रीमती सुधा पुत्री प्रेमनारायण

निवासी सटई रोड उत्तरप्र म०प्र०

विरुद्ध

म०प्र० शासन

--- आवेदक

--- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1234/III/2014

जिला छतरपुर

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

1-5-2014

यह निगरानी अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक (अपठनीय)/अ-19/99-2000 स्व.प्रे.नि. में पारित आदेश दि. 7-8-2000 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम सूरजपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 120/4 ख रकबा 4.90 एकड़ के वह वर्ष 1970 से भूमिस्वामी है किन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना अपर कलेक्टर ने भूमि बन विभाग के स्वामित्व पर दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश दिये है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जावे।

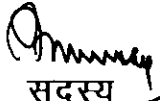
3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 7-8-2000 के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम सूरजपुरा तहसील छतरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 120/4 ख रकबा 4-90 एकड़ जो बन विभाग के अधिसूचित क्षेत्र में है, आवेदक के अनुसार उसे तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 60/अ-19/83-84 से पट्टा मिला है। तहसीलदार छतरपुर ने प्रतिवेदन क्रमांक 343/बी-121 / 99-2000 दिनांक 22-7-2000 प्रस्तुत कर उक्तांकित भूमि बन





विभाग के संसूचित क्षेत्र में होकर बन क्षेत्र की होना बताया है, जिस पर अपर कलेक्टर, छतरपुर ने आदेश दिनांक 7-8-2000 से तहसीलदार के प्रतिवेदन को सही होना मानकर बन भूमि दर्ज करने के आदेश दिये हैं। वैसे भी बन विभाग की भूमि किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं की जा सकती।

4/ उपरोक्त कारणों से अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक (अपठनीय)/अ-19/99-2000 स्व.प्रे.नि. में लिया गया निर्णय दिनांक 7-8-2000 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।


सदस्य